ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः ३

झारखंड के दो युवाओं की जल संचयन तकनीक भुंगरू की वैश्विक स्तर पर चर्चा

भुंगरू
निर्भरता से स्वतंत्रता

रविवारीय, 11 - 17 अक्टूबर 2020 वर्ष- दो, अंक-10, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

राँची रेल मंडल में कोविड-19 के खिलाफ 'जन आंदोलन अभियान' चलाया

रांची : मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ 'जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) अजीत सिंह यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित एवं सभी शाखा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अभियान के अंतर्गत रांची रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर मुख्यता रांची, हटिया, मुरी रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सभी रेल कर्मचारियों ने, तथा मंडल के अन्य सभी कार्य स्थलों में कोविड-19 के खिलाफ 'जन आंदोलन अभियान' के अंतर्गत सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शपथ ली। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं रेल यात्रियों को जागरूक करना है ।

कांके डैम बचाने का संघर्ष

संवाददाता

रांची :शहर में स्थित सबसे बड़े जलाशय कांके डैम को बचाने के लिये दो अक्टूबर से कांके डैम संरक्षण समिति का अनिश्चित कालीन धरना सह सत्याग्रह लगातार जारी है।

पिछले तीन साल से कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी घेराबंदी करने, डैम तक पहुंचने वाले सभी नालों के सीधे प्रवेश पर रोक लगाने,डैम की साफ सफाई तथा प्रदूषण मुक्त करने के अलावा जिन रैयत परिवारों का जमीन डैम निर्माण में गया उन विस्थापितों/स्थानीय मछुआरों को मछली पालन का अधिकार दिलाने के लिए 2 अक्टूबर से कांके डैम के किनारे,सोसो फुटबॉल मैदान में यह धरना सह सत्याग्रह किया जा रहा है। समिति के अमृतेश पाठक ने आम लोगों से भी इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है।

इस आंदोलन में मुख्यत: डैम के आस पास की बस्तियों के लोगों की ही सहभागिता है। आम रांचीवासी जो इस डैम के जल पर ही जिंदा है वो दूर से ही इस आंदोलन को देख रहे हैं। अब तक दस दिन से चल रहे इस आंदोलन से सरकार के किसी नुमाइंदे में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है।

कांके डैम रांची का गौरव रहा है। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद से इस विशाल जलाशय की स्थिति बदतर होती गयी। अतिक्रमण कर इसके किनारों की जमीने बेच दी गयी, ग्रीनलैंड के अलावा इसके कैचमेंट तक में मकान बना लिये गये। कुछ साल पहले अतिक्रमण कर बनाये गये मकानों को तोड़ा गया था, पर कांके रोड और रातू रोड की ओर से आज भी अतिक्रमण जारी है। इसका पानी प्रदूषित है और अतिक्रमण की मार से कांके डैम कराह रहा है।

शहर के बीच इतने बड़े जलाशय की उपलब्धता से कभी छठ महापर्व के समय तकरीबन सारे शहरवासियों का यह प्रिय जलाशय था। जनप्रतिनिधियों ने भी यहां अतिक्रमण रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और सरकारी अफसरों ने अतिक्रमण की खबर को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हाल के कुछ दिनों से इसके किनारे से अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। अब देखना है कि कांके डैम संरक्षण समिति के आंदोलन से सरकार जगती या नहीं?

कांके डैम को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त कर रैयतों के मछलीपालन की मांग को लेकर धरने पर बैठे समिति के सदस्य

मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा:अमृतेश पाठक

कांके डैम बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चित कालीन धरना सह सत्याग्रह के दसवें दिन डैम के चारों ओर दीप जलाकर जलाशय की पूजा की गई। साथ ही पतरागोंदा,सोसो,लक्ष्मी नगर ,हेसल,हथिया गौंदा,टिकली टोला, मिशिर गोंदा, मिशन गली, कठल गोंदा के सैकड़ों लोगों ने हाथ में मशाल थामकर डैम की स्वच्छता,सुंदरता और सुरक्षा का संकल्प तथा एक जुटता का प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर्ता अमृतेश पाठक ने कहा कि पिछले दस दिनों से दर्जन भर गाँवों के लोग धरना देकर डैम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। आज मशाल जला कर लोगों ने संबंधित विभाग और नगर निगम को घोर अंधकार और निराशा से बाहर निकलकर इस जलाशय को बचाने तथा दर्जन भर गाँव के रैयत/विस्थापित/स्थानीय मछुआरों को रोजगार देने का आग्रह किया है।

मशाल जला कर विरोध का नेतृत्व करने वालों में मनोज कुमार पुटू,प्रदीप लकडा,रमेश मुंडा,मनोज उरांव,मंटू मुंडा,आजू मुंडा,बिरसा मुंडा,करन मुंडा,शिवा मुंडा,कृष्णा पाहन,विकास मुंडा,पिंटू मुंडा,प्रशांत पांडे,किशोर महापात्रा,सियाराम सिंह ,गौरीशंकरआदि षाडंगी ने किया। सबने एकजुटता प्रदर्शन कर कहा है कि जब तक माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी स्वयं यहाँ आकर हमलोगों की मांग पूरी नहीं करेंगे धरना जारी रहेगा।

सूर्यमन्दिर में उमड़ने लगी पर्यटकों की भीड़

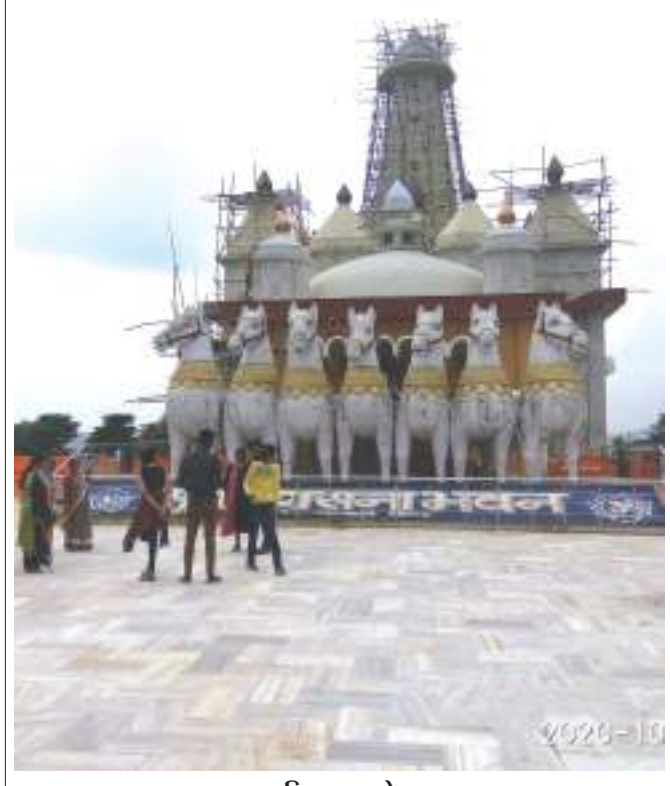

सिदाम महतो

बुण्डू: कोरोना के कारण लगभग 6 माह तक बन्द बुण्डू स्थित सूर्य मन्दिर को बीते 8 अक्टूबर को खोल दिया गया । पहले की तरह लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है।लोग भगवान भास्कर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।शनिवार को भी कई पर्यटक मन्दिर परिसर पहुंचे।

गुजरते लम्हे को कैमरे में कैद करते देखे गए

हालाँकि मन्दिर का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है ।इस कारण पर्यटक परिसर के चारों ओर घूम नही सकते हैं। सौंदर्यीकरण का कार्य अभी कुछ दिन और चलेगा। मन्दिर के पण्डित सत्यनारायण पाठक कहते कि, सरकार के दिशा-निर्देश का पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। एक साथ भीड़ नही करनी है। आपस में दुरी बनाकर कर रहना है।

पण्डितजी कहते हैं कि पहले से अब बहुत कुछ बदल गया है , प्रसाद वितरण नही होगा, हम किसी को तिलक भी नही लगा सकते हैं। ज्ञात हो कि 8 अक्टूबर से कंटेन्मेंट जोन के बाहर के धार्मिक स्थल खुल गए हैं। इसमें सरकारी दिशा-निर्देश का अनुसरण करना होगा।

रोजगार

नए मछली पालकों के लिए तालाब की व्यवस्था

आशीष कुमार

ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों के पास तालाब नहीं है और वह मछली पालन करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक है। उनके पास एक बड़ी समस्या तालाब की व्यवस्था करना है । उन्हें समझ में नहीं आता है कि तालाब की व्यवस्था कैसे होगी ऐसे में उन्हें जानना चाहिए कि पूरे राज्य में लगभग 16719 सरकारी तालाब है। जिनकी बंदोबस्ती 3 वर्षों के लिए प्रखंड स्तरीय मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के साथ की जाती है, परंतु यदि समितियां सक्षम नहीं है अथवा लेने के लिए इच्छुक नहीं है तो वैसी स्थिति में खुले डाक के द्वारा तालाबों की बंदोबस्ती की जाती है। इसका लाभ उठाकर किसान भाई सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती डाक बोलकर 3 वर्षों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे झारखंड राज्य में लगभग 116305 निजी क्षेत्र में तालाब है जिनमें कुछ तालाब सामुदायिक है तो कुछ तालाब निजी स्वामित्व में है।

यदि किसान भाई अपने गांव के आसपास उपलब्ध तालाबों की जानकारी प्राप्त कर उनकी बंदोबस्ती ले ले तो तालाब की समस्या दूर हो सकती है। इसके अतिरिक्त नए तालाब बनाने के लिए राज्य सरकार की योजना चल रही है जिसमें प्रति एकड़ ₹500000 की लागत पर 70% अनुदान की व्यवस्था है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 80% अनुदान की व्यवस्था है। इस योजना का भी लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा भी नए तालाब निर्माण की योजना दी जा रही है। इसमें प्रति हेक्टेयर ₹700000 की योजना पर 40% अनुदान दिया जाएगा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को 60% अनुदान दिया जाएगा ।

नया तालाब निर्माण का लाभ लेने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है जो अंचल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होता है, उसके बिना योजना की स्वीकृति असंभव है। किसान भाई ऊपर बताए गए तालाबों की उपलब्धता और नया तालाब निर्माण की योजनाओं का लाभ उठाकर तालाब की समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं और मछली पालन प्रारंभ कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए आप लेखक से संपर्क कर सकते हैं।

लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं

Ph. 9430783037

email:

coomar2012@gmail.com

झारखण्ड में सामुदायिक जैविक खेती की कार्य योजना बनी

हम कुछ लोगों ने साथ मिल कर रांची, झारखण्ड में सामुदायिक जैविक खेती की कार्य योजना बनाई है । हम लोगों ने खेती लायक एक भूमि का चुनाव किया है जहां सामूहिक तौर पर जैविक सब्जियों का उत्पादन करेंगे ।

यह एक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपितु अपने खुद के परिवार के लिए शुद्ध रसायन मुक्त सब्जियों को उपलब्ध कराने का प्रयास है। इसमें एक मासिक शुल्क आपस में इकट्ठा किया जायेगा, कुछ लोगों को भी रखेंगे तथा अपने श्रम को भी लगायेंगे खुद की जैविक खेती के लिए । बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होगा ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन हो सके। अनुमानित योगदान प्रति माह करीब ३०००/- होने की उम्मीद है एक परिवार के लिए जिसमे २-५ सदस्य हों (बच्चों सहित) इसके अतिरिक्त शुरू में एकमुश्त राशि भी लगेगी। श्रमिक निवास, गाय शेड इत्यादि के निर्माण के लिए जो की सब लोग मिल कर वहन करेंगे। हर एक को सप्ताह में एक दिन स्वयं का श्रमदान भी करना होगा। अतिरक्त सब्जियों को बाजार में बेचा जा सकता है जिसकी आय भी खेती में लगाई जायगी । आगे सबकी राय पर अनाज, दालों तथा तिलहन को भी शुरू किया जा सकेगा । जिन सुधीजनों को इसमें रूचि हो अथवा जैविक / प्राकृतिक कृषि सीखने को इच्छुक हों तो दिनाक १३ अक्टूबर, २०२० तक निम्नांकित जानकारी फणि कुमार जी (सवयंसेवक) को WhatsApp से भेज दें:

नाम:

परिवार में व्यस्क:

बच्चे (१० वर्ष से कम):

पता:

दूरभाष नंबर:

WhatsApp नंबर:

इसके उपरान्त एक आभासी (ऑनलाइन) बैठक रखी जायेगी जिसमें आगे की कार्य रणनीति निर्धारित होगी जिसकी जानकारी इच्छुक व्यक्तियों को दे दी जाएगी ।

चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन से लीक हुए तेल का पर्यावरण पर असर नहीं

झारखंड के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में हुए तेल रिसाव के मामले में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 सितंबर को एनजीटी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में टीम ने तेल रिसाव से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का भी आंकलन किया है। गौरतलब है कि तेल रिसाव की यह घटना 15 अक्टूबर, 2019 को घटित हुई थी। जब तेल को चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की साइट पर अनलोड किया जा रहा था उसी वक्त कनेक्टिंग ह्यू पाइप में दरार आ गई थी, जिससे तेल लीक होने लगा थो यह तेल बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम के रास्ते से दामोदर नदी में पहुंच गया था।

इस लीक हुए तेल को जल निकासी चैनल और नदी से एकत्र किया गया था, जिसे बाद में ड्रम में इकठ्ठा कर लिया गया थो साथ ही तेल के रिसाव को रोकने के लिए फ्लाई ऐश का भी उपयोग किया गया था।

समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और जानकारी दी है कि कहीं भी हाइड्रोकार्बन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा, पास के कृषि क्षेत्र पर भी पर्यावरणीय नुकसान के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले तेल को कम विषैला माना जाता है और लम्बे समय में इसके क्या परिणाम सामने आएंगे उसके विषय में और अधिक अध्ययन करने की जरुरत है।

अपना पूरा दिन कहां खर्च करते हैं भारतीय!

एनएसओ ने जारी की सर्वे रिपोर्ट

एनएसओ ने पहली बार टाइम यूज इन इंडिया सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोगों की दिनचर्या के बारे में जानकारी जुटाई गई है

गांवों में रह रही महिलाएं लगभग 5 घंटे अपने परिवार की देखभाल में खर्च कर देती हैं। गांवों में रह रही महिलाएं लगभग 5 घंटे अपने परिवार की देखभाल में खर्च कर देती हैं।

भारतीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) ने 9 अक्टूबर को टाइम यूज इन इंडिया 2019 सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि भारतीय अपना पूरा दिन किन-किन गतिविधियों में खर्च करता है। एनएसओ ने पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की है।

एनएसओ ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच यह सर्वे किया था। इसमें 1,38,799 घरों के 4,47,250 लोगों को शामिल किया गया। इसमें परिवार में छह साल से अधिक उम्र के सभी सदस्यों की दिनचर्या का विश्लेषण किया गया। इनमें 2,73,195 ग्रामीण और 1,74,055 शहरी शामिल थे। सर्वे के दौरान सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक के कामकाज के बारे में बातचीत की गई।

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एक दिन में सबसे अधिक 726 मिनट अपनी देखभाल पर खर्च करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक यानी 737 मिनट ग्रामीण पुरुष अपनी देखभाल पर खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट में स्वयं की देखभाल में सोना, खाना-पीना, सेहत पर ध्यान देना, इलाज कराना, अपनी देखभाल के लिए कहीं आना-जाना आदि शामिल है।

इसके बाद सबसे अधिक समय रोजगार और उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। एक दिन में 429 मिनट रोजगार और उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं। इस मामले में गांवों वालों के मुकाबले शहर वालों को ज्यादा समय देना पड़ रहा है। शहर के लोगों को दिन के 485 मिनट इस पर खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक शहरी पुरुषों को 514 मिनट (लगभग 9 घंटे) रोजगार के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके मुकाबले ग्रामीण पुरुषों को 434 मिनट खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं को 317 मिनट और शहरी महिलाओं को

375 मिनट रोजगार व उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए बिताने पड़ रहे हैं।

एक और दिलचस्प आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अपने दिन के 301 मिनट अपने परिवार के सदस्यों के लिए खर्च कर देती हैं और इसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। जबकि इनके मुकाबले शहरी महिलाएं 293 मिनट अपने परिवार के सदस्यों के लिए खर्च करती हैं। इस मामले में ग्रामीण पुरुष 98 मिनट और शहरी पुरुष 94 मिनट ही खर्च करते हैं। हालांकि लोग समाज के काम करने, सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाने, ईमेल, चैट आदि पर भी बड़ा समय खर्च कर रहे हैं।

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लोग दिन में औसतन 143 मिनट सोशलाइजिंग एंड कॉम्युनिकेशन, सामाजिक भागीदारी और धार्मिक कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। जबकि संस्कृति, मास मीडिया और खेलों पर 165 मिनट खर्च किए जा रहे हैं।

सीखने, शिक्षा पर भी बड़ा समय खर्च किया जा रहा है। औसतन दिन का 424 मिनट पर लर्निंग पर खर्च किए जा रहे हैं। इस मामले में शहरी, गांव वालों से थोड़ा आगे हैं। गांवों में 422 मिनट लर्निंग तो शहरों में 430 मिनट खर्च किए जा रहे हैं।

अच्छे मॉनसून के बावजूद कितना जलसंरक्षण ?

झारखंड में इस वर्ष संतोषजनक बारिश हुयी है और ज्यादतर तालाब, झीलें पानी से भरे हुये दिख रहे हैं, पर रांची में हकीकत का सामना तो हर साल गर्मियों में होता है। जब शहर के आस पास तीन तीन विशाल झीलों के होने के बावजूद जलसंकट गहराता है, डीप बोरिंग कई सौ किमी की खुदाई के बाद भी फेल हो जाते हैं। हाल ही में यह तथ्य सामने आया कि धुर्वा डैम के किनारे रिंग रोड के इंजीनियरिंग में गलती के कारण अब डैम में बारिश का पानी सही मात्रा में एकत्र नहीं हो पा रहा है और वह पानी किसानों के खेत में जाकर बाढ सी स्थिति पैदा कर उनकी फसलें बर्बाद कर रहा है। यही कारण है कि धुर्वा डैम से पानी की सप्लाई में राशनिंग होती रही है। क्योंकि इस विशाल जलाशय में उसकी क्षमता लायक जल एकत्र नहीं हो पा रहा है।

कुछ ऐसा ही हाल गोंदा जलाशय का भी है। इसके निर्माण के बाद आज तक इसकी सफाई नहीं हुई इस कारण से इसमें गाद बैठ गया और इसके जल संचय की क्षमता कम होती गयी। अब कम बारिश में भी यह लबालब भर जाता है और इसका फाटक खोलना पड़ता है।

बड़ा तालाब में भी सौंदर्यीकरण के नाम पर इसके किनारों पर एक चारदिवारी बना दी गयी इस कारण से यहां भी जल संचय नहीं हो पाता।

पहले भी कहा गया है कि तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिये होगा। चीन हमारी सीमा पर सैनिक जमावड़ा कर रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि चीन हिमालय के जलस्त्रोंतो को मोड़ कर अपनी ओर करना चाह रहा है। वह यहां से विशाल जलराशि को सुरंगो के माध्यम से तिब्बत और देश के उन इलाकों तक ले जाना चाहता है जहां जल की कमी है। वह तो सिंधु नदी का रूख भी मोड़ देना चाहता है ताकी वह पाकिस्तान न पहुंचे। ब्रह्मपुत्र के स्त्रोत को वह बंद करने की क्षमता रखता है। यानि वह पानी के लिये युद्ध भी लड़ने को तैयार है।

ऐसे में जल के महत्व को समझ आम लोगों को भी जलसंरक्षण के लिये सोचना आवश्यक है।

यह रांची का दुर्भाग्य ही है कि जब हम रांची पहाड़ी पर चढ कर शहर का अवलोकन करते हैं तो चारो ओर कोई न कोई जलाशय अवश्य नजर आता है इसके बावजूद गर्मियों के शुरूआत में ही यहां जलसंकट और पानी की सप्लाई में राशनिंग की नौबत आती है। अब मॉनसून जाने को है और जाड़ों में राजधानी को जलसंकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर यह जरूर सोंचने की बात है कि अच्छे मॉनसून के बाद भी हमने कितना जल संचय किया?

4.9 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का उपयोग पालतू जानवरों के भोजन के लिये होता है

शोधकर्ताओं का अनुमान है की हर साल पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियों के सूखे भोजन के लिए 4.9 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है। यदि इस कृषि भूमि के विस्तार को समझें तो यह जमीन ब्रिटेन के आकार से लगभग दोगुनी है। इस जमीन से उतना भोजन उत्पन्न होता है जोकि इन जानवरों के लिए जरुरी खाद्य पदार्थ की बिक्री का करीब 95 फीसदी होता है।

इसके साथ ही शोध में इस उद्योग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का भी पता लगाने का प्रयास किया गया है। अनुमान है कि पालतू जानवरों से जुड़े खाद्य उद्योग से जितना उत्सर्जन हो रहा है, वो मोज़ाम्बिक और फिलीपींस जैसे देशों द्वारा उत्सर्जित की जा रही ग्रीनहाउस गैसों से भी ज्यादा है। दुनिया भर में जैसे-जैसे जानवरों को पालतू बनाने का शौक बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इन जानवरों का पेट भरने के लिए उनसे जुड़ा खाद्य उद्योग भी फलता-फूलता जा रहा है। ऐसे में यह उद्योग पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना सस्टेनेबल है, उसका विश्लेषण भी जरुरी हो जाता है। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने अमेरिका और यूरोप में उपलब्ध पालतू जानवरों के 280 से भी ज्यादा खाद्य पदार्थों और उसमें मौजूद घटकों का विश्लेषण किया है। गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोप दुनिया भर में बिकने वाले जानवरों के खाद्य पदार्थों के दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पता चला है कि करीब आधे शुष्क खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए फसलों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मक्का, चावल और गेहूं प्रमुख हैं। जबकि बाकी के निर्माण के लिए मांस मछली का उपयोग किया जा रहा है।

आधुनिक खेती ने खाद्य उत्पादन को ही बना दिया जलवायु के लिए ख़तरा

नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार नाइट्रोजन फ़र्टिलाइज़र जलवायु के लिए इस कदर ख़तरा बन गए हैं कि इनके चलते पेरिस समझौते के तहत जलवायु से जुड़े लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखते

आज से 111 साल पहले 1909 में जब जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर ने दुनिया को बताया कि नाइट्रोजन और हायड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनती है, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने वाले और बेहतर करने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों का आधार बनने वाली यह खोज आगे चल के पूरी मानवजाति के लिए एक भारी खतरा बनेगी। आज, 2020 में विज्ञान हमें बता रहा है कि नाइट्रोजन फ़र्टिलाइज़र जलवायु के लिए इस कदर ख़तरा बन गए हैं कि इनके चलते न सिर्फ़ पेरिस समझौते के तहत जलवायु से जुड़े लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखते, बल्कि इन उर्वरकों ने खाद्य उत्पादन तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य उत्पादन पर जलवायु को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगे तो यह बड़ी विकट परिस्थिति की ओर इशारा करती है। भारत तो वो देश है जो हमेशा से देसी कृषि तकनीकों का समर्थक रहा है लेकिन बाज़ारवाद के दबाव में आधुनिक कृषि तकनीक और उर्वरक हमें ही खाने को तैयार बैठे दिखते हैं।

दरअसल, नेचर मैगज़ीन में छपे ऑबर्न विश्वविद्यालय के ताज़ा शोध से पता चलता है कि नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन कि वजह से पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पूरा न होने का खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में भोजन के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता या कंसन्ट्रेशन्स बढ़ रहा है। यह एक ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक प्रभावी है और मानव जीवन की तुलना में वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है।

यह खोज ऑबर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ साइंसेज़ में एनड्रयू कार्नेजी फेलो और इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड ग्लोबल चेंज रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर हैक्विन टीयान के नेतृत्व में हुए एक अध्ययन का हिस्सा है। ये अध्ययन आज दुनिया की सबसे प्रचलित विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर हैक्विन टीयान ने 14 देशों के 48 अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ को साथ लेकर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव की छत्रछाया में इसका सह-नेतृत्व किया। अध्ययन का उद्देश्य और शीर्षक था, "वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड स्रोतों का एक व्यापक मात्राकरण और हानि", इस प्रभावकारी ग्रीनहाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड का अभी तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन जो इसके उत्पादन के भी स्त्रोतों और उससे होने वाले नुकसानों की पूरी जानकारी देता है ।

टीयान के ऑबर्न सहयोगी जिसमे प्रोफेसर शुफेन पान, पोस्टडॉक्टोरल फेलो रोंगिंग जू, हाओ शि, युआनज़ी याओ और स्नातक छात्र नाइकिंग पैन भी शामिल हैं, ने और 57 वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने सह-लेखक के रूप में काम किया। ये अध्ययन, जलवायु परिवर्तन को तेजी से प्रभावित करने वाली एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है: नाइट्रस ऑक्साइड पूर्व-औद्योगिक स्तरों के मुकाबले 20 प्रतिशत तक बढ़ा है इसके अलावा विभिन्न मानव गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन के कारण हाल के दशकों में इसकी वृद्धि में और तेजी आई है।

प्रोफेसर हैक्विन टीयान ने कहा, "इसकी वृद्धि का सबसे प्रमुख कारक है कृषि। इसके अलावा जानवरों के लिए भोजन और फ़ीड की बढ़ती मांग भी वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को और बढ़ाएगी। अध्ययन से यह भी जानकारी मिलती है कि वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का है। अध्ययन में पाया गया कि चीन, भारत और अमेरिका में सिंथेटिक उर्वरकों के इस्तेमाल से यहाँ उत्सर्जन सबसे अधिक है, जबकि पशुधन से बनने वाली खाद से होने वाले उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का है। उत्सर्जन की सबसे अधिक विकास दर उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से ब्राजील, चीन और भारत में पाई गई, जहां फसल उत्पादन और पशुधन की संख्या में वृद्धि हो रही है।

अध्ययन का सबसे आश्चर्यजनक परिणाम जिससे सभी सह-लेखक सहमत थे कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की वजह से वर्तमान पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस अकॉर्ड में निर्धारित किये लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं हैं, क्योंकि इसका उत्सर्जन नियमों के अनुरूप नहीं है । 195 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित, इस समझौते का उद्देश्य है कि इक्कीसवीं सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि से होने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना और तापमान को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है।

हालांकि, ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस में एक सीनियर रिसर्च स्कोलर और अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन इनिशिएटिव की पूर्व निदेशक विल्फ्रिएद विनीवार्टर कहते हैं, ''नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के अवसर अब भी मौजूद हैं''। उन्होंने आगे कहा, "यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले दो दशकों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को सफलतापूर्वक कम किया है।

ग्रीनहाउस गैसों और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और उर्वरक उपयोग को सुधारने के लिए बनाई गई औद्योगिक और कृषि नीतियां प्रभावी साबित हुई हैं। फिर भी यूरोप में और साथ ही विश्व स्तर पर और भी प्रयासों की आवश्यकता होगी।

वहीँ ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट साइंस सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक के रूप में अध्ययन के सह-नेता जोसेप कानडेल्ल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह शोध महत्वपूर्ण और जरूरी है। वो कहते हैं, "यह नया तुलनात्मक विश्लेषण वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग और दुरुपयोग के तरीकों पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने कि ओर इशारा करता है और हमें आग्रह करता है कि हम खाने को व्यर्थ न करें और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में और अधिक प्राकृतिक तकनीकों को अपनाएं।

अब तक का सबसे गर्म महीना रहा सितम्बर: कॉपरनिकस

कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) ने ऐलान किया कि सितंबर 2020 दुनिया में अब तक का सबसे गर्म सितंबर रहा। सितंबर 2020 पूरी दुनिया में सितंबर 2019 के मुकाबले 0.05 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। जिससे इस तरह इस बीच, साइबेरियन आर्कटिक में तापमान में सामान्य से ज्यादा की बढ़ोत्तरी जारी रही और आर्कटिक सागर पर बर्फ का आवरण दूसरे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया।

सी3एस के विश्लेषण से मिले डाटा से जाहिर होता है कि सितंबर 2020 मानक 30 वर्षीय जलवायु संदर्भ अवधि के तहत सितंबर में दर्ज किए गए औसत तापमानों के मुकाबले 0.63 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इस तरह सितंबर 2019 के मुकाबले इस साल इसी महीने में तापमान 0.05 डिग्री सेल्सियस और सितंबर 2016 के मुकाबले 0.08 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इससे पहले सितम्बर 2019 सबसे गर्म सितम्बर रहा, जबकि वर्ष 2016 में गुजरा सितंबर दूसरा सबसे ज्यादा गर्म सितम्बर रहा। सी3एस को यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (ईसीएमडब्ल्यूएफ) द्वारा यूरोपीय कमीशन की ओर से लागू किया गया है। यह यूरोपीय तथा वैश्विक स्तर पर तापमानों की निगरानी करता है।

पूरे यूरोप में भी सितंबर में औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह इससे पहले सबसे गर्म सितंबर के तौर पर दर्ज किए गए वर्ष 2018 के इसी महीने के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। महाद्वीप के ज्यादातर इलाकों में सितंबर में दर्ज तापमान औसत से ज्यादा रहा। खासतौर से दक्षिण पूर्वी यूरोप में।

सी3एस के वैज्ञानिकों ने यह भी जाहिर किया कि अब तक के सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज किए गए वर्ष 2016 में और 2020 में ईयर टू डेट आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त बहुत थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों वर्षों में एक जनवरी से 30 सितंबर के बीच औसत वैश्विक तापमान विसंगतियां बहुत मिलती-जुलती हैं। वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 ज्यादा गर्म है। अब ला नीनो जैसे जलवायु पैटर्न यह तय करेंगे कि क्या वर्ष 2020 अब तक का सबसे गर्म साल बन जाएगा। साइबेरियन आर्कटिक में सितंबर माह में तापमान में सामान्य से ज्यादा बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है। इससे तपिश का क्रम बरकरार है और इसकी वजह से वसंत की शुरुआत से ही एक बहुत बड़े क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर असर पड़ा है। हालांकि साइबेरिया और आर्कटिक में साल दर साल तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन अध्ययन से यह पता चला है कि इस साल दर्ज की गई सापेक्ष तपिश अपने पैमाने और दृढ़ता के मामले में अभूतपूर्व है।

सी3एस हर महीने समुद्री बर्फ की भी निगरानी करता है और उस-के डेटा से इस बात की पुष्टि होती है कि सितम्बर में आर्कटिक सागर में जमी बर्फ के क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है। वर्ष 2012 में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गयी थी। वर्ष 1979 में सेटेलाइट से निगरानी का सिलसिला शुरू होने के बाद से आर्कटिक में समुद्री बर्फ के क्षेत्रफल में खासी कमी आयी है। बर्फ के दायरे में गिरावट का यह रुख साल के सभी महीनों में देखा जा सकता है लेकिन खासकर सितम्बर के महीने में बर्फ का यह आवरण साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। जलवायु सम्बन्धी कारकों की वजह से समुद्री बर्फ का खालिस वार्षिक चक्र वसंत की शुरुआत से ही शुरू होकर गर्मियों के अंत तक चलता है, जब हिमावरण अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। आमतौर पर ऐसा सितम्बर में होता है। उसके बाद बर्फ का आवरण फिर से बढ़ने लगता है और सामान्यतः मार्च तक यह उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है।

कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के निदेशक कार्लो बुओटेम्पो ने बताया ''वर्ष 2020 के जून और जुलाई के महीनों में आर्कटिक सागर पर बर्फ की परत में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। यह गिरावट उन्हीं इलाकों में हुई है जहां सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इसकी वजह से इस साल खास तौर पर बर्फ के आवरण में कमी आई है। रिकॉर्ड गर्मी और आर्कटिक सागर में बर्फ की मात्रा में गिरावट को मिलाकर देखें तो इससे जाहिर होता है कि दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्र में और अधिक व्यापक तथा बेहतर निगरानी कितनी जरूरी है। सी3एस हर महीने जलवायु संबंधी बुलेटिन प्रकाशित करता है, जिसमें वैश्विक सतह वायु तापमान तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य अन्य कारकों में होने वाले बदलावों का जिक्र किया जाता है। प्रकाशित किए जाने वाले सभी तथ्य कंप्यूटर जेनरेटेड अध्ययनों पर आधारित होते हैं। इन अध्ययनों के लिए सेटेलाइट, पानी के जहाज, विमान तथा दुनिया भर में स्थित मौसम केंद्रों से मिलने वाले अरबों पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है।

सितंबर 2020 में सरफेस एयर टेंपरेचर

यूरोप में और वैश्विक स्तर पर सितंबर 2020 तक का सबसे गर्म सितंबर रहा। यह वर्ष 2019 के सितंबर के मुकाबले 0.05 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म रहा।

दुनिया भर के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा। इनमें उत्तरी साइबेरिया के तट से दूर इलाके पश्चिम एशिया के क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के इलाके शामिल हैं।

पूर्वी इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर में औसत से ज्यादा ठंड रही जो ला नीनो के अनुरूप है।

निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का काउंटडाउन

दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट गठित ईपीसीए ने उद्योगों और निर्माण परियोजनाओं को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की आहट पर बचाव उपायों के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की पुष्टि के बाद दिल्ली में हवा का मिजाज बिगड़ना शुरू हो गया था। वहीं दिल्ली में आठ अक्तूबर, 2020 के बाद से लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पाई गई। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तत्काल कदम उठाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ईपीसीए ने यह दिशा-निर्देश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत दिए हैं। जीआरएपी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक चरणबद्ध योजना है। यह 15 अक्तूबर से दिल्ली-एनसीआर में प्रभावी होगी। ईपीसीए ने दिल्ली और इससे लगे हुए शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बुनियादी और आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही ईपीसीए की ओर से औद्योगिक व निर्माण गतिविधि संबंधी बड़ी परियोजनाओं को धूल प्रबंधन के लिए तय नियमों और मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के नजफगढ़ में नाले को रेत और मिट्टी से भरने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

एनजीटी ने 7 अक्टूबर को डॉ धर्मेंद्र सिंह द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है मामला दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के न्यू गोपाल नगर का है जहां कुछ लोगों द्वारा रेत और मिट्टी से एक नाले को भरा जा रहा था, जिससे मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने 2 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दक्षिण दिल्ली नगर निगम से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट को सूचित किया है कि उसने इस मामले में जरुरी कार्रवाई की थी इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें आगे कोई और आदेश जारी करने की जरुरत नहीं है।

रूस के अवाचा खाड़ी समंदर में 95 प्रतिशत समुद्री जीवों की मौत

रूस में प्रशांत महासागर की अवाचा खाड़ी में बड़ी प्राकृतिक तबाही होने की बात सामने आई है। यहां बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में समुद्री जीव मृत मिल रहे है।

बताया जा रहा है कि अवाचा खाड़ी के समंदर में 95 प्रतिशत समुद्री जीवों की मौत हो चुकी है. जिसे रूस की अब तक की सबसे बड़ी समुदी त्रासदी कहा जा रहा है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि समुद्री जीवों की मौत की वजह क्या है. अवाचा खाड़ी के Khalaktyrsky बीच पर ऑक्टोपस, सील, केकड़े, मछलियों समेत कई जीव मृत मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस समुद्री तबाही की फोटो वायरल हो रही है. जिसके बाद प्रकृति प्रेमी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

द मास्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वैज्ञानिक समुद्री जीवों की मृत्यु के पीछे प्रदूषण को वजह बता रहे हैं तो वहीं कुछ वैज्ञानिक समंदर के अन्दर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने की बात कह रहे हैं. इस घटना की जांच करने के लिए एक स्पेशल कमीशन गठित कर दिया गया है.शुरूआती जांच में यह पता लगा है कि ना केवल समुद्री जीवों बल्कि इंसानों पर भी इस प्राकृतिक तबाही का असर हुआ है. कुछ स्थानीय मछुआ-रों और सर्फर्स ने बताया कि पानी से किसी पेस्टीसाइड जैसी गंध आ रही है. वहीं, समंदर में सर्फिंग करने वाले कुछ लोगों ने उल्टियां, गले में दर्द और आंखों में जलन होने की भी बात कही है.पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने पानी के चार टेस्ट किए जिसमें यह पाया गया कि पानी में कोई पेट्रोलियम जैसा पदार्थ है. जिसकी वजह से समुद्री जीवों की मौत हुई है. स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ दिनों से सील, ऑक्टोपस और समुद्री मछलियां मरकर बीच पर आ रही हैं. इस तरह की घटना उन्होंने पहली बार देखी है. वहीं, क्षेत्रीय गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने इस बारे में कहा कि तट के आसपास के समंदर में पानी विषाक्त हो गया है. ग्रीनपीस ने भी समुद्री जीवों के विलुप्त होने की चेतावनी दी है. सोलोडोव ने आगे कहा कि विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना कुछ विषैले पदार्थों के फैलने की वजह से हुई है. क्योंकि बीच के पास ही सैन्य परीक्षण स्थल, रेडगिनो है। जो समुद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अगस्त में यहां ड्रिल की गई थी. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।

आवासीय परियोजना के कारण सिसवन नदी के प्रवाह में आ रही है बाधा

1 अक्टूबर 2020 को एनजीटी में ओमैक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला उठाया गया था। यह डेवलपर 'द लेक' नामक एक आवासीय परियोजना की स्थापना कर रहा है। जिस परियोजना के लिए उसने कथित तौर पर सिसवन नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डाली थी उसने नदी के एक हिस्से को ग्राम भरोजियान में भर दिया गया था और इसे गांव कांसला, उप तहसील माजरी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में पास के एक अन्य स्थान पर मोड़ दिया था।

आवेदक ने गूगल इमेजेस का सहारा लेते हुए दिखाया है कि वर्ष 2003 में जहां एक नाला था उसपर सड़क का निर्माण कर दिया गया थो जबकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए उसपर किसी पुलिया का निर्माण भी नहीं किया गया था। जिसके कारण बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ गई थी और वास्तव में उसके कारण बाढ़ आई भी थी।

मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने जारी किया आदेश

एनजीटी ने 9 अक्टूबर, 2020 को मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के मामले में आदेश जारी कर दिया है इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण होने के बावजूद वहां सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेत खनन किया जा रहा थो अपने आदेश में एनजीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए रेत खनन किया जा रहा हो, उसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरुरी है ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि वहां अवैध रेत खनन होता है तो स्थानीय प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

एनजीटी ने सीवेज प्रदूषण के मामले में राजस्थान नगर निगम से तलब की रिपोर्ट

एनजीटी ने 7 अक्टूबर को राजस्थान नगर निगम के मुख्य सचिव को 21 जनवरी 2021 से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है मामला अजमेर के कुंदन नगर का है जहां अनधिकृत कॉलोनी से सीवेज का पानी खुले में बह रहा थो इस मामले में नगर निगम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था।गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने 24 जुलाई, 2019 को अजमेर नगर निगम से एक तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। जिसे नगर निगम ने सबमिट नहीं किया थो इसके बाद कोर्ट ने नगर निगम को 26 फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया थो साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि यदि नगर निगम रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तो कोर्ट के पास अजमेर नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है जिसमें उसका वेतन तक रोका जा सकता है

कृषि पर हुये अंतर्राष्ट्रीय वेब सम्मेलन में रांची के रथीन भद्रा एवं राजा बागची के जल संचयन तकनीक भुंगरू को मिली वैश्विक सराहना

झारखंड के दो युवाओं की जल संचयन तकनीक भुंगरू की वैश्विक स्तर पर चर्चा

संवाददाता

झारखंड और रांची के लिये यह गौरव का विषय है कि हाल ही में कृषि पर हुये अंतर्राष्ट्रीय वेब सम्मेलन में जल संचयन की नायाब तकनीक भुंगरू को विश्व के सभी देशों ने बहुत ही सराहा और इसमें रूचि ली। ग्रीन रिवोल्ट ने पहले भी भुंगरू के बारे में विस्तार से एक खबर प्रकाशित किया है। अब भुंगरू को राजा बागची एवं रथीन भद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी है।

यह वेब कांफ्रेंस कोविड-19 काल में कृषि में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल विषय पर आयोजित था। जो 4 अक्टूबर से 6 ऑक्टूबर 2020 तक आयोजित था। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया की कई यूनिवर्सिटी तथा लोगो ने भाग लिया जैसे बांग्लादेश , मलेशिया , इंडोनेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरब. इस इंटरनेशनल वेब कॉन्फ्रेंस में कुल 721 शोधार्थियों ने अपना अपना शोध प्रस्तुत किया और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सबों को अपने रिसर्च के बारे में बताया कि कैसे इससे कृषि को फायदा हो सकता है ।

721 शोधार्थियों में से एक झारखंड के भूंगरु "पानी की खेती" को भी जगह दी गई और सबसे मुख्य स्पीकर में रखा गया , भारत से ले कर इजिप्ट तक सभी देशों ने झारखंड के भूंगरु "पानी की खेती" पद्धति के बारे में भूंगरु के आविष्कारक राजा बागची तथा रथीन भद्रा से बहुत ही बारीकी से समझा और कई सवाल भी किये और इस पद्धति से हो रहे फायदे के बारे में जान कर भूंगरु के जलसंरक्षण के इस पद्धति की काफी प्रसंशा किया और इससे "BOON FOR FARMERS" का नाम दिया और इसे AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY DEVLOPMENT SOCIETY ने अपने सोविनियर के पृष्ठ संख्या 27,28 तथा 29

में भी लिखा। कई देशों के कृषि विश्वविद्यालयों ने इस पद्धति को बढ़ावा देने की बात भी कही और टीम भूंगरु (राजा बागची / रथीन भद्रा) को आमंत्रित भी किया। अपने प्रेजेंटेशन में भूंगरु के आविष्कारक राजा बागची ने बताया कि किसान आज क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।

अत्यधिक अव्यवस्थित बारिश के कारण खेतो में जल जमाव हो जा रहा है जिसके कारण किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो जा रहे है वहीं पानी के कमी के कारण रबी का फसल नही हो पाता है जिसके कारण उनके पास और कोई विकल्प ही नही बच रहा है। कर्ज चुकाने के लिये या तो वे दिहाड़ी मजदूर बन शहर की ओर पलायन कर रहे है या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है। अगर इन जल जमाव वाले खेतो के आस पास कही भी भूंगरु होता तो अपने सक्शन और इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से सारे जल जमाव वाले पानी को सोंख लेता और उसे अपने खास संचयन तकनीक से एक जगह संचय कर लेता इससे किसानों की खाड़ी फसल बर्बाद होने से बच जाती और भूंगरु के माध्यम से रबी के फसल के लिए भी पानी प्राप्त हो जाता। इससे किसानों को साल में दो फसलों का लाभ मिलता और उनकी आय भी दुगुनी हो जाती तो फिर क्यों कोई किसान आत्महत्या करेगा या पलायन करेगा ?

अब हमें पानी की खेती भी करनी होगी

राजा बागची ने बताया कि एक भूंगरु से करीब 40 लाख लीटर से ले कर 4 करोड़ लीटर तक जल संचयन किया जा सकता है और जितना भी काम भूंगरु ने झारखंड में किया है। सभी जगहों पर करीब - करीब एक से डेढ़ करोड़ लीटर का कैचमेंट मिला है साधारण भाषा मे अगर कहें तो एक तालाब में 15 से 20 लाख लीटर पानी होता है और जब भूंगरु डेढ़ करोड़ लीटर की बात करता है तो करीब करीब एक भूंगरु दस तालाब को हंगरी स्टार्टा में संचय करता है और जब इतना पानी जमीन के अंदर रहता है तो इसका मॉइस्चराइजर ऊपर आता है और बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है और खेतों में नमी बरकरार रहती है इससे "CLIMATE CHANGE MITIGATION" भी कहते है । भूंगरु के डायरेक्टर रथीन भद्रा ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि दुनिया को वैज्ञानिक तरीके से जल संचयन करना चाहिए जिससे कि सही में फायदा हो जल संचयन का और उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया कि अगर हम अब भी नही चेते और भूंगरु जैसे साइंटिफिक जल संचयन को नही अपनाया तो वो दिन दूर नही की पानी के लिये हम त्राहिमाम करेंगे और यह हमे एक और विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा । रथीन भद्रा ने बताया कि पानी को हम बना नही सकते है, पानी को हम पैदा नही कर सकते है पानी को हम सिर्फ और सिर्फ संचय ही कर सकते है और अब समय आ गया है कि जैसे हम दाल , चावल, गेंहू, बाजरे की खेती कर रहे है वैसे ही अब हमें "पानी की खेती" भी करनी ही होगी।

सीसीएल ने हातमा बस्ती में मास्क व सैनिटाईजर का किया वितरण

रांची : सीसीएल में 'स्वच्छता माह'के अंतर्गत जागरूकता अभियान जारी है।'' स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत'' के संदेश के साथ सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता माह, 2020''स्वच्छता ही सेवा"के रूप में मनाया जा रहा है ।इसी कड़ी में आज हातमा बस्ती, कांके रोड, रांची में आमजन के बीच स्वच्छता जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीसीएल प्रबंधन द्वारा मास्क एवं सैनिटाईजर का वितरण किया गया। साथ ही हातमा बस्ती के निवासियों को स्वच्छता संबंधी जानकारी व अपने घरों व आसपास को स्वच्छ रखने के फायदे बताये गये। सीएसआर टीम द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना महामारी में स्वच्छता का एक विशेष स्थान है और साफ-सफाई से संक्रमण से बचा जा सकता है। टीम द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान रखनें के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभी को स्वच्छता की शपथ'दिलवायी गयी। सीसीएल की ओर से मुख्य प्रबंधक (सीएसआर) के.ए. सुन्दर, मुख्य प्रबंधक (असैनिक) एस.एस. लाल, गौरव तिवारी, श्रीमती श्वेता हांसदा, प्रवीण एवं अन्य उपस्थित थे।

एनजीटी ने संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए कहा

एनजीटी ने 28 सितंबर, 2020 को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय को 31 दिसंबर, 2020 से पहले पश्चिमी घाट में मौजूद पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए कहा है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, सोनम फेंटसो वांग्दी और विशेषज्ञ नागिन नंदा की पीठ ने कहा है कि चूंकि राज्यों ने कुछ क्षेत्रों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र से बाहर रखने के लिए कहा है, इसलिए इसमें देरी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है गौरतलब है कि एनजीटी का यह आदेश पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की अधिसूचना को अंतिम रूप देने में जारी देरी के मद्देनजर दिया गया है जोकि पिछले आठ वर्षों से लंबित है।

अदालत ने कहा कि 'विकास' की आवश्यकता का दावा करने वालों द्वारा इसके अधिक से अधिक बहिष्कार की मांग की गई है, जबकि 'पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता' ऐसी मांगों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है।

एनजीटी ने 22 नवंबर, 2019 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए। उस सुनवाई के दौरान इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) डिवीजन के सलाहकार, एमओईएफ और सीसी से जुड़े व्यक्ति मौजूद थे इस आदेश में कहा गया था कि इस मामले पर सुनवाई जारी है और इसे 31 मार्च से पहले सकारात्मक रूप से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में अपनी रिपोर्ट दायर करे और मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी, 2021 से पहले की जाएगी।

अनटूवार्ड इंसीडेंट (अप्रिय घटना) विषय पर सेफ्टी सेमिनार

रांची : 06अक्टूबर को अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन)एम एम पंडित की मुख्य उपस्थिति में अनटूवार्ड इंसीडेंट (अप्रिय घटना), माल गाड़ियों के डिब्बों के दरवाजे का खुला रहना विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया।

आज के परिपेक्ष्य में माल गाड़ियों की गति पहले की तुलना में बढ़ गई है, मानवीय भूल या किसी अन्य कारण से या परिचालन के दौरान माल गाड़ियों के डिब्बों के दरवाजे कभी-कभी खुल जाते हैं, जिसके कारण पटरी के बगल पर स्थित सिग्नल पोस्ट या रेलवे के अन्य संपत्तियों से इसके टकराने की संभावना बनी रहती है, जिससे परिचालन में बाधा उत्पन्न होती है एवं रेलवे संपत्ति का नुकसान होता है। अतः इस तरह की घटना ना हो तथा इसके लिए ली जाने वाली सावधानियों के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि जब कोई भी माल गाड़ी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, उससे पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि मालगाड़ी के डिब्बों के सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए गए हैं।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेफ्टी सेमिनार में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवनीश, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता श्री दीपांजल सरकार एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव ने अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का सख्त निर्देश दिया।इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेफ्टी सेमिनार में परिचालन, वाणिज्य, विद्युत एवं रेल सुरक्षा बल विभाग के अधिकारी एवं सुपरवाइजर भी सम्मिलित थे ।

महिला सशक्तिकरण: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम :एसोचैम

रांची : उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति ने देश के व्यापार और आर्थिक विकास की जनसांख्यिकीय विशेषताओं में परिवर्तन किया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में दूसरों को प्रेरित करने और देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देश में एक संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों की सतत विकास की आवश्यकता है।

ये बातें 9 अक्टूबर को एसोचैम के महिला सशक्तिकरण पर नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट: आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम के आयोजन में कही गयी।

इस कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय निदेशक एसोचैम भरत जायसवाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि एसोचैम एक जिम्मेदार चैंबर है। कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री दीपिका कुमारी थी। उन्होंने महिलाओं को खेल और अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि खराब वित्तीय परिस्थितियों के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन केवल अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण उसने सफलता हासिल की है। उसने कहा कि माता-पिता को अपने अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी लड़कियों का समर्थन करना चाहिए। की नोट अड्रेस सुश्री अंबा प्रसाद, विधायक, बड़कागांव, झारखंड द्वारा दिया गया । उन्होंने कहा कि महिलाओं को जीवन के हर पहलू में बढ़ावा और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं कुटीर उद्योग में अद्भुत काम कर रही हैं और इसी तरह उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा साबित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और समाज में निर्णय लेने में भाग लेना चाहिए।

सुश्री प्रिया दूबे, आईपीएस प्रशिक्षण, झारखंड द्वारा विशेष संबोधन दिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी जरूरत शिक्षा है और प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर महिला के पास अपने फोन में शक्ति ऐप होना चाहिए और जरूरत के समय इसका उपयोग करना चाहिए।

इस आयोजन में भारत और विदेश के प्रख्यात वक्ता भी अपने विचार साझा किए जिसमें सुश्री अर्चना गर्ग, सीईओ / संस्थापक, अर्चना के साथ पावर टॉक, सुश्री पूजा जायसवाल, चैपर्सन एसोचैम झारखंड महिला सशक्तिकरण परिषद, सुश्री आस्था किरण, सह-अध्यक्ष, एसोचैम, झारखंड महिला सशक्तिकरण परिषद, सुश्री अर्शी अयूब मोहम्मद जवेरी, सीनियर सलाहकार शाही परिवार दुबई, सुश्री कल्पना चौधरी, सह-अध्यक्ष, एसोचैम झारखंड महिला सशक्तिकरण परिषद, सुश्री प्रतिमा पायल सिंह, एमवे बिजनेस ओनर, संदीप मुखर्जी, सह अध्यक्ष, एसोचैम झारखंड खाद्य, कृषि और डेयरी विकास परिषद मुख्य थे।

रेलवे सुरक्षा बल ने नाबालिग को रेस्क्यू कर हेल्पलाइन को सुपुर्द किया

रांची : 6 अक्टूबर को 'नन्हे फरिश्ते'' समूह, रेलवे सुरक्षा बल, रांची मंडल के द्वारा एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 14 वर्ष नाम उर्मिला कुमारी पता सेमरा लोहरदगा की रहने वाली, जो हटिया रेलवे स्टेशन पर गोवा जाने के लिए इधर - उधर घूम रही थी को रेस्क्यू कर रांची हेल्पलाइन को सुपुर्द किया गया।

कोयला मंत्रालय ने अनुसंधान व विकास पर किया वेबसाइट लांच

संवाददाता

रांची : कोयला मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और कोयला सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास उद्यमों (प्रयत्नों) के लिए अनुसंधान संस्थानों को आकर्षित करने हेतु शुक्रवार को एक वेबसाइट लांच किया गया है। अनिल कुमार जैन, सचिव (कोयला), भारत सरकार ने मंत्रालय की स्टैंडिंग साईंटिफिक रिसर्च कमेटि की 56वीं बैठक के दौरान वेबसाइट https://scienceandtech.cmpdi.co.in/ को लांच किया। सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), जो कोल इंडिया आ-रएंडडी का अंग है, ने इस वेबसाइट का डिजाइन और विकास किया है।

यह वेबसाइट कोयला क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और ज्ञान को बढ़ावा देने एवं इसके प्रसार में मदद करेगा।'' अनिल कुमार जैन ने इस वेबसाइट की लॉचिंग के समय उपुर्यक्त बात कही। उन्होंने वेबसाइट के विकास में सीएमपीडीआई के प्रयासों की प्रशंसा की और वेबसाइट पर कोयला सेक्टर में आरएंडडी के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वेब लिंक इस वेबसाइट में दर्शाने का सुझाव दिया। इस वेबसाइट में विभिन्न रूपों में कोयला अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक रूप से दिशा-निर्देश प्रदर्शित किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपेक्षित ढंग से अपना प्रस्ताव सौंप सके। इसमें पूरी की गई परियोजनाओं की सूची तथा परिणाम तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं को भी दर्शाया गया है जिससे कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे तथा परियोजनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसमें कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र से जुड़े फोटो, वीडियो एवं समाचार क्लिपिंग भी दिए गए हैं तथा इस वेबसाइट पर भिन्न-भिन्न प्रकाशन भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट में देश की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आने वाले समय में कोयला अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र (थ्रस्ट एरिया) भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय रूप से, कोयला मंत्रालय, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों में अपने कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) योजना के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, कोयला परिष्करण और उपयोग, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध क्षेत्रों आदि में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। कोयला मंत्रालय इन विषयों पर शोध कार्य करने के लिए निधि भी प्रदान करता है।

अनुसंधान परियोजनाएं, वर्तमान में, कोयला और लिग्नाइट उत्पादक कम्पनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, एनआरएससी, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नए क्षेत्रों की पहचान कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा की गई है और सीएमपीडीआई के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है, जिसके आधार पर पूरे वर्ष के लिए अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

फोटो न्यूज

निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता से बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता

''स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत'' के संदेश के साथ सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबरतक स्वच्छता माह, 2020''स्वच्छता ही सेवा"के रूप में मनाया जा रहा है । इसी कड़ी मेंऑनलाईन निबंध एवं पेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जेएसएसपीएस (झारखंड सरकार एवं सीसीएल की संयुक्त पहल), सीसीएल के लाल- लाडली सहित सीसीएल कमांड क्षेत्रों में स्थित विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्हें ''स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने में भारतीय नागरिक की भूमिका''विषय पर निबंध एवं पेंटींग के माध्यम से अपने विचार एवं रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए दिया गया था। बच्चों ने बहुत ही सुन्दर लेख एवं चित्र के माध्यम से अपनी परिकल्पना, सुझाव व विचारों को कागज पर उतारा। भारत सरकार की मुहिम 'स्-वच्छता ही सेवा'के अंतर्गत सीएमडी पी.एम. प्रसाद के मार्गनिर्देशन में 'स्वच्छता माह'में कर्मियों सहित आमजन को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक (सीएसआर) ए.के. सिंह, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) के.ए. सुन्दर, मुख्य प्रबंधक (सीएसआर) एस.एस. लाल, गौरव तिवारी, श्रीमती निकिता भदानी, श्रीमती श्वेता हांसदा, मार्यो एक्का, प्रवीण एवं अन्य के सहयोग से किया जा रहा है।

शरीर का डीटॉक्स क्या है ?और इसे क्यों करना चाहिए

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

भाग -1

"शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने की पद्धति " को डीटॉक्स कहते है । अगर इसे हम सरल भाषा में समझें तो ये शरीर को अन्दर से साफ करने की एक प्रक्रिया है । शरीर को हम ऊपर से हर रोज साफ करते है या कभी-कभी तो दिन में दो बार भी सफाई हो जाती है ,परन्तु आन्तरिक अंगों का क्या?आन्तरिक अंगों की गन्दगी को हम देख नहीं पाते हैं। जब आन्तरिक अंग मलिन हो जाता है तो हमें कई स्वस्थ सम्बंधित समस्याएं आने लगती है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं जैसे हर मशीन को सर्विसिंग(मरम्मत)की आवश्यकता होती है ,अगर हम समय पर इसकी मरम्मत न करें तो मशीन सुचारू रूप से नहीं चलती, ठीक वैसे ही डीटॉक्स हमारे शरीर की सर्विसिंग है।

हमारा शरीर दूषित किन कारणों से होता है।

●हवा के द्वारा-आजकल हवा इतनी दूषित है कि ये हमारे स्वस्थ को प्रभावित करती है, जब हम सांस लेने है तो सारा दूषित हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करता है जिससे कारण फेफड़ों से सम्बंधित कई बिमारियों होती हैं।

● पानी के द्वारा- जितना हवा में प्रदूषण है उतना ही पानी भी दूषित है ।ऐसा बोलते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन जब जल ही दूषित हो जाये तो हमारा शरीर भी दूषित हो जाता है। दूषित पानी हमारे किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करता है और जिससे कारण हमे किडनी सम्बंधित कई बिमारियॉ हो सकती है जैसे किडनी में पत्थर, यूरिन इंफेक्शन इत्यादि।

●खाद्य पदार्थों के द्वारा-आजकल खेती में कीटनाशकों और रासायनिक का काफी प्रयोग होता है। पहले हमें सिर्फ मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां मिलती थी लेकिन आजकल हर मौसम में सारी फल और सब्जियां उप्लब्ध होती है। खेती की पैदावार भी बढाने लिए रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिए धीमा जहर के जैसे काम करता है और हमारे लीवर के साथ साथ पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

●त्वचा के द्वारा- त्वचा के द्वारा भी काफी रासायनिक हमारे शरीर के अन्दर जाता है। सौन्दर्य प्रसाधन के इस्तेमाल से काफी रासायनिक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जल और हवा में प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है।

आज हमने देखा कि हमारा शरीर दूषित किन कारणों से होता है और इसको अंदर से साफ करने के लिए डीटॉक्स करना चाहिए। अगले हफ्ते हम डीटॉक्स के तरीकों के बारे मे बात करेगें। क्या है ?और इसे क्यों करना चाहिए।

"शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने की पद्धति " को डीटॉक्स कहते है ।अगर इसे हम सरल भाषा में समझें तो ये शरीर को अन्दर से साफ करने की एक प्रक्रिया है । शरीर को हम ऊपर से हर रोज साफ करते है या कभी-कभी तो दिन में दो बार भी सफाई हो जाती है ,परन्तु आन्तरिक अंगों का क्या?आन्तरिक अंगों की गन्दगी को हम देख नहीं पाते हैं। जब आन्तरिक अंग मलिन हो जाता है तो हमें कई स्वस्थ सम्बंधित समस्याएं आने लगती है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं जैसे हर मशीन को सर्विसिंग(मरम्मत)की आवश्यकता होती है ,अगर हम समय पर इसकी मरम्मत न करें तो मशीन सुचारू रूप से नहीं चलती, ठीक वैसे ही डीटॉक्स हमारे शरीर की सर्विसिंग है।

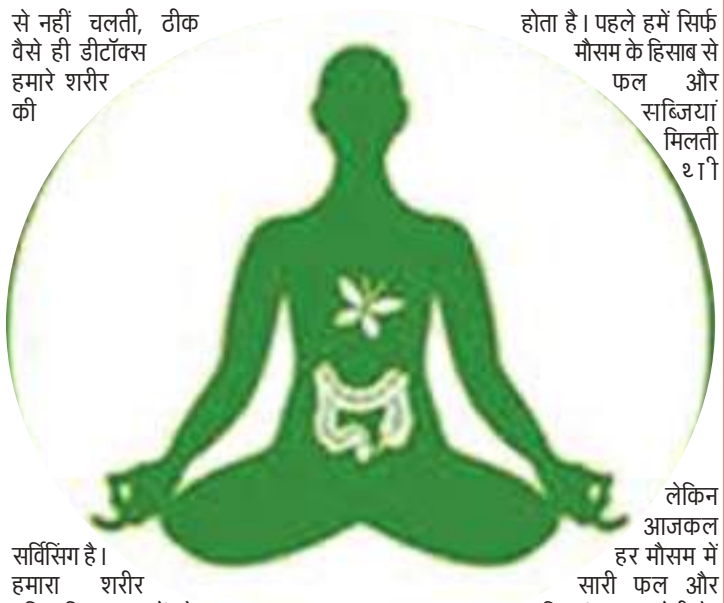

हमारा शरीर दूषित किन कारणों से होता है।

●हवा के द्वारा-आजकल हवा इतनी दूषित है कि ये हमारे स्वस्थ को प्रभावित करती है, जब हम सांस लेने है तो सारा दूषित हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करता है जिससे कारण फेफड़ों से सम्बंधित कई बिमारियों होती हैं।

● पानी के द्वारा- जितना हवा में प्रदूषण है उतना ही पानी भी दूषित है ।ऐसा बोलते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन जब जल ही दूषित हो जाये तो हमारा शरीर भी दूषित हो जाता है। दूषित पानी हमारे किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करता है और जिससे कारण हमे किडनी सम्बंधित कई बिमारियॉ हो सकती है जैसे किडनी में पत्थर, यूरिन इंफेक्शन इत्यादि।

●खाद्य पदार्थों के द्वारा-आजकल खेती में कीटनाशकों और रासायनिक का काफी प्रयोग होता है। पहले हमें सिर्फ मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां मिलती थी लेकिन आजकल हर मौसम में सारी फल और सब्जियां उप्लब्ध होती है। खेती की पैदावार भी बढाने लिए रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिए धीमा जहर के जैसे काम करता है और हमारे लीवर के साथ साथ पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

●त्वचा के द्वारा- त्वचा के द्वारा भी काफी रासायनिक हमारे शरीर के अन्दर जाता है। सौन्दर्य प्रसाधन के इस्तेमाल से काफी रासायनिक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जल और हवा में प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है।

आज हमने देखा कि हमारा शरीर दूषित किन कारणों से होता है और इसको अंदर से साफ करने के लिए डीटॉक्स करना चाहिए। अगले हफ्ते हम डीटॉक्स के तरीकों के बारे मे बात करेगें।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

फरीदाबाद की वेस्टा हाइट्स परियोजना में बार बार किया गया नियमों का उल्लंघनः एनजीटी

एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और सोनम फेंटसो वांग्दी की पीठ हरियाणा में चल रहे आवासीय परियोजनाओं के मामले में अपना आदेश जारी कर दिया है उन्होंने अपने आदेश में कहा कि इन आवासीय परियोजनाओं में पर्यावरण से सम्बंधित मानदंडों का बार-बार उल्लंघन किया गया है, जो कि अत्यंत गंभीर है

मामला फरीदाबाद के सेक्टर-86 में गांव बसलवा का है जहां वेस्टा हाइट्स नामक परियोजना चल रही थी इस मामले में कोर्ट पर्यावरण मंजूरी और जल (प्रदूषण पर नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की शर्तों के हो रहे उल्लंघन को देख रही थी।कोर्ट के अनुसार इस परियोजना के लिए जल अधिनियम 1974 के तहत दी गई काम करने की मंजूरी मार्च 2018 में समाप्त हो गई थी। इस परियोजना के लिए बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर्याप्त नहीं थे और उनसे आगरा नहर में सीवेज का ओवरफ्लो हो रहा था।

अरुणाचल प्रदेश ने एनजीटी को सौंपी अपनी रिपोर्ट

अरुणाचल प्रदेश ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों के मामले में अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है इस रिपोर्ट में जैव विविधता प्रबंधन अधिनियम, 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन और सभी स्थानीय निकायों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों (पीबीआर) की तैयारी से जुडी जानकारी भी दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश ने एनजीटी को सूचित किया कि राज्य ने 9 अगस्त, 2019 को दिए एनजीटी के आदेश का 100 फीसदी पालन कर लिया है उसने कुल 1806 समितियों का गठन कर लिया है साथ ही 1806 पीबीआर भी तैयार कर लिए हैं साथ ही राज्य ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 1 फरवरी, 2020 को उसपर लगाया गया जुर्माना भी माफ कर दिया जाए।

बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं यूपी के अस्पताल

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 1027 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से 564 में बायो मेडिकल कचरे को एकत्र करने के लिए उचित जगह नहीं है

उत्तर प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बायो मेडिकल कचरे के प्रबंधन पर न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर की अध्यक्षता वाली निरीक्षण समिति की एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट शैलेश सिंह बनाम शीला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर और अन्य के मामले में मूल याचिका संख्या 710/2017 में पारित एनजीटी के आदेश के अनुपालन में थी। मामला उत्तर प्रदेश द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (बीएमडब्ल्यू नियम, 2016) के प्रावधानों का पालन न करने से संबंधित है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 में बीएमडब्ल्यू पर नजर रखने की प्रणाली निर्धारित की गई थी - जिसमें सभी रंगीन बैगों पर बार-कोड लगे होने चाहिए। ट्रकों की आवाजाही पर एक जीपीएस के जरिए नजर रखी जानी चाहिए। हालांकि लखनऊ में शुरु के छोटे से समय अंतराल में इसका उपयोग हुआ, अब कोई भी ऑपरेटर बार-कोडिंग प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहा है। जो उत्पन्न आंकड़ों की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (एचसीएफ) में बड़े संरचनात्मक कमियां देखी गई हैं। जिसके कारण कई बीएमडब्ल्यू नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 100 से अधिक बेड की संचालन क्षमता वाले 530 एचसीएफ में से लगभग 452 एचसीएफ में एसटीपी / ईटीपी नहीं है। सरकारी सुविधाओं में भी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) से युक्त 1027 एचसीएफ में से - 564 एचसीएफ में बायो मेडिकल कचरे को एकत्र करने के लिए उचित जगह नहीं है। जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का संबंध है, 3620 पीएचसी में से केवल 628 पीएचसी में ही कचरा दबाने के लिए गहरे गड्ढे हैं। जिला अस्पतालों में ईटीपी निर्माण करने की गति बहुत धीमी थी और इस साल केवल 40 जिला अस्पतालों ने ही ईटीपी का निर्माण किया गया है। 2483 एचसीएफ हैं जिन्होंने बीएमडब्ल्यू नियमों के तहत इजाजत नहीं ली है। इनमें से 441 सरकारी एचसीएफ हैं।

रेडियोधर्मी पदार्थों के निपटान में एक महत्वपूर्ण कमी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग को मानक प्रोटोकॉल का विकास करना चाहिए और सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए क्षमता का निर्माण करना चाहिए।

निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में हितधारकों में क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। अस्पतालों में प्रदूषण एक निरंतर चुनौती है और संक्रमण की प्रकृति और सीमा बदलती रहती है, अभी नई मुसीबत कोविड-19 है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि क्षमता निर्माण कार्यशालाओं को सभी हितधारकों - डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, अन्य अस्पताल कर्मचारियों, प्रयोगशाला कर्मचारियों, रक्त बैंक कर्मचारियों, निजी चिकित्सकों, नर्सिंग होम और एचसीएफ के लिए एक सतत आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए।

जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को अर्जेंटीना ने दी स्वीकृति

एजेंसियां

अर्जेंटीना ने जिस जीएम गेहूं की फसल को मंजूरी दी है उसे एचबी 4 नाम दिया है। इसे अर्जेंटीना की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोसीरस ने तैयार किया है। अर्जेंटीना जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को उगाने और उसकी खपत को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यह जानकारी अर्जेंटीना के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में सामने आई है जिसके अनुसार अर्जेंटीना ने सूखे से निपटने में सक्षम जीएम गेहूं की फसल को मंजूरी दे दी है गौरतलब है कि दुनिया भर में अर्जेंटीना गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है

अर्जेंटीना के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि "दुनिया भर में यह पहला मौका है जब किसी देश ने जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को उगाने और उसकी खपत को मंजूरी दी है।

अर्जेंटीना ने जिस जीएम गेहूं की फसल को मंजूरी दी है उसे एचबी 4 नाम दिया है इसे अर्जेंटीना की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोसीरस और नेशनल यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग की मदद से विकसित किया गया है इस फसल (एचबी 4)पर एक दशक तक किए गए परीक्षण से पता चला है कि सूखे की स्थित में यह फसल, अन्य की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा उपज देती है।

हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार इसका भविष्य क्या होगा उसपर अभी संदेह है क्योंकि जिस तरह से जीएम फसलों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है उसके चलते उपभोक्ता इसे आसानी से नहीं अपनाएंगे ऐसे में इनको उगाना और बेचना चिंता का एक बड़ा विषय है

क्या होती हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितनी हैं सुरक्षित

जीएम फसलें या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें वो फसलें होती हैं, जिनके जीन (डीएनए) में बदलाव कर दिया जाता है जिससे फसलों के उत्पादन और उसमें मौजूद आवश्यक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जा सके साथ ही वो प्रकृति की विषम परिस्थितयों को भी झेलने में सक्षम हो सकें।

जीएम फसलों पर सबसे बड़ा सवाल उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर है यह खाद्य पदार्थ कितने सुरक्षित हैं, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएम फसलों में विभिन्न जीवों और पौधों से जीन (डीएनए) लेकर उन्हें खाद्य फसलों में डाला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ''विदेशी'' डीएनए विषाक्तता, एलर्जी, पोषण और अनायास प्रभावों जैसे जोखिम पैदा कर सकते हैं, जोकि स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जीएम फसलों के साथ एक समस्या यह भी है कि इसमें इच्छित परिवर्तनों के साथ अनचाहे परिवर्तनों के होने की सम्भावना भी बनी रहती है।इसी खतरे को देखते हुए भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों ने जीएम फूड के लिए ''सावधानीपूर्ण'' दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने इसके अनुमोदन और लेबलिंग के लिए कड़े नियम निर्धारित किए हैं। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने जीएम फूड को लेबल करना अनिवार्य कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं के पास खाने का चुनाव करते समय विकल्प मौजूद हों।

नए सोलर पैनल डिजाइन से 10 गुना ज्यादा सौर ऊर्जा बनेगी

दयानिधि

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र लगातार हल्के पदार्थों में सोलर सेल के प्रकाश अवशोषण को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है।

सूर्य के प्रकाश का अवशोषण सौर सेल तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए नैनो फोटोनिक संरचनाएं उनकी क्षमता में सुधार को लेकर एक बहुत अच्छी तकनीक के रूप में उभरी हैं। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि चेकरबोर्ड लाइनों में सौर पैनलों को डिजाइन करने से उनकी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता 125 फीसदी बढ़ जाती है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि पतले, हल्के और अधिक लचीले सौर पैनलों का उत्पादन अधिक हो सकता है, जिनका उपयोग अधिक घरों को बिजली देने में किया जा सकता है। यह अध्ययन यॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में, लिस्बन के नोवा विश्वविद्यालय की साझेदारी में आयोजित किया गया। अध्ययन में जांचा गया कि सोलर सेल में सूर्य के प्रकाश के अवशोषण पर अलग-अलग सतह के डिजाइन ने किस तरह प्रभाव डाला है। यह अध्ययन ऑप्टिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

वैज्ञानिकों ने पाया कि चेकरबोर्ड डिज़ाइन से प्रकाश के फैलने में सुधार हुआ, जिसने प्रकाश के अधिक अवशोषित होने की संभावना को बढ़ाया। अवशोषित प्रकाश से ही बिजली बनती है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र लगातार हल्के पदार्थों में सोलर सेल के प्रकाश अवशोषण को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है। इनका उपयोग छत की टाइलों से लेकर नाव और अलग-अलग जगह लगे उपकरणों तक के उत्पादों में किया जा सकता है। सोलर ग्रेड सिलिकॉन- का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए पतले सेल बनाने और सतह के डिजाइन को बदलने से उन्हें सस्ता और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।

भौतिक विभाग से डॉ. क्रिश्चियन शूस्टर ने कहा हमने पतले सोलर सेल के प्रकाश अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक सरल तकनीक बनाई है। हमारे अधिक परिष्कृत डिजाइनों ने प्रकाश अवशोषण को बढ़ाया है। गहरे पैनल अधिक प्रकाश को अवशोषित करते है। समतल संरचना के पैनल कम प्रकाश अवशोषित करते है।

डॉ. शूस्टर ने बताया कि हमारा डिजाइन सौर सेल के लिए अधिक प्रकाश अवशोषित करने के सभी प्रासंगिक पहलुओं को पूरा करता है। यह सरल और व्यावहारिक संरचनाओं को बनाने की बात करता है। यह डिजाइन सौर सेल को पतले, लचीली सामग्री में जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए अधिकतर जगहों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का अधिक अवसर पैदा करता है।

अध्ययन से पता चलता है कि डिजाइन सिद्धांत न केवल सौर सेल या एलईडी क्षेत्र में, बल्कि शोर से बचने के लिए ढाल, हवा से न टूटने वाले पैनल, न फिसलने वाली सरफेस, बायोसेंसिंग एप्लिकेशन और परमाणु शीतलन जैसे उपयोगों के लिए भी इस्-ाका प्रयोग किया जा सकता है।

डॉ. शूस्टर ने कहा कि इस सिद्धांत से हम अवशोषक सामग्री की समान मात्रा के साथ दस गुना अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते है। दस गुना पतली सौर सेल फोटोवोल्टिक्स को तेजी से बढ़ा सकती हैं, जो सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं, और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकती हैं। सिलिकॉन के कच्चे माल को संसोधित कर ऊर्जा सुचालकता को बढ़ाया जा सकता है, दस गुना पतली सिलिकॉन सेल न केवल आसानी से संसोधित हो जाती हैं, बल्कि इसमें खर्च भी कम होगा, इसलिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जिसमें पर्यावरणीय जोखिम सबसे कम होंगे।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।